मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

फरीदाबाद की मज़दूर बस्तियां : कृष्णा नगर 2
मरीज़ रहित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी 4
बोहनी तो अच्छी हुई, लेकिन सफर लम्बा है 5
हिंदी एक फलती फूलती भाषा है... 6
बीके अस्पताल में सविता यादव के संरक्षण में फलते-फूलते दलाल 8

वर्ष 36 | अंक 45 | फरीदाबाद | 18-24 सितम्बर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

कोर्ट के आदेश से 27 लाख के गबन का केस दर्ज

डीईओ मुनीष चौधरी को सर्व शिक्षा अभियान में घोटाले के भूत ने पकड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 13 सितम्बर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह की अदालत ने ज़िला शिक्षा अधिकारी के वरुद्ध 27 लाख के गबन का मुकदमा दर्ज करने के लिये पुलिस आयुक्त को आदेश दिये हैं। 14 सितम्बर को थाना सेक्टर 17 में भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 402, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 7ए, 10 लगाई गई है।

डीईओ मुनीष चौधरी का अधिकांश सेवाकाल शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान में बीता है। सर्वविदित है कि यह अभियान अपने आप में ही घोटालों व गबन का पर्यायवाची है। मुनीष जैसी भ्रष्ट अधिकारियों को लूट कमाई का इससे बढिया

डीईओ मुनीष : भ्रष्टाचार, अब तेरा ही आसरा

अवसर और कहां मिल सकता था? वर्ष 2005-6 के आसपास जब इनकी तैनाती यहां पर हुई थी तो करीब 25 लाख की ग्रांट चेक सरकार की ओर से इनके पास आया था। इस ग्रांट के द्वारा इन्हें विभिन्न स्कूलों व उनके छात्रों के लिये कई तरह के काम कराने थे।

अपने नाम से आये चेक को मुनीष चौधरी ने सीधे अपने निजी बैंक खाते में जमा करा दिया। कुछ माह पश्चात विभाग के किसी सयाने बाबू ने इन्हें चेताया कि सरकारी रकम को इस तरह से सीधे-सीधे नहीं हड़पा जाता। सरकारी रकम को अपने निजी खाते में रखना ही अपने आप में अपराध है। सलाह पर अमल करते हुए मुनीष ने उक्त रकम को तुरंत अपने खाते से निकाल कर सरकारी खाते में जमा कराया। उसके बाद शुरू हुआ झूठे बिलों का फर्जीवाड़ा।

विभाग में मौजूद कुछ सतर्क आंखे

शेष पेज चार पर

एसीएस महावीर सिंह को क्या सांप सूंघ गया

अति गंभीर धाराओं में मुनीष चौधरी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने क बावजूद हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने अभी तक मुनीष को पद से हटाया तक नहीं है। इसके विपरीत कुछ माह पूर्व जब रितु चौधरी का इस पद से तबादला आदेश जारी किया था तो टेलीफोन पर टेलीफोन और धमकी पर धमकी देकर तुरन्त पद खाली करा लिया गया था। अब उन्हें क्या सांप सूंघ गया है।

मुनीष चौधरी ने नौकरी को कभी घर की खेती से अधिक नहीं समझा

फरीदाबाद ज़िले की रहने वाली मुनीष चौधरी ने 1988 में बतौर टीजीटी नौकरी की शुरूआत की थी। इस दौरान हमेशा अपने घर के नजदीक वाले स्कूल में ही अपनी तैनाती कायम रखी थी। वर्ष 2003 में प्रिंसिपल, 2011 में खंड शिक्षा अधिकारी, 2019 में डिप्टी डीईओ 2021 में डीईईओ तथा जून 2022 में डीईओ के पद पर तैनात हो गई। मजे की बात तो यह है कि इस सारे सेवा काल के दौरान, मात्र चार माह पलवल लगाने के अलावा सारी नौकरी फ़रीदाबाद शहर में की है।

नौकरी चाहे स्कूल में की हो या विभागीय दफ्तर में, इन्होंने कभी नौकरी को नौकरी नहीं समझा। महीनों-महीनों स्कूल से फर्लो मारकर अपने बच्चों के साथ कोटा में रहना पड़ा तो भी कभी इन्होंने छुट्टी के लिये आवेदन नहीं किया। यहां तक कि विदेश यात्रा करने तक के लिये इन्होंने कभी विभाग से छुट्टी अथवा स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं समझी। अपने व अपने पति धर्म सिंह के राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धों के बल पर मुनीष सदैव अपने विभाग में हावी रही है। कभी किसी प्रिंसिपल अथवा डीईओ की हिम्मत नहीं हुई कि इनसे कभी कोई पूछ-ताछ कर सके।

जानकार बताते हैं कि पिछले दिनों जब रितु चौधरी यहां बतौर डीईओ तैनात थी तो उन्होंने मुनीष को दफ्तर आने व कुछ काम करने को कहना शुरू किया तो तत्कालीन एडीसी सतबीर मान से लेकर मुख्यालय में बैठे टुक्कड़खोरों ने उल्टे डीईओ रितु को ही धमकाना शुरू कर दिया। मुनीष की पहुंच तो देखिये कि इस बाबत मुख्यालय से डीईओ के नाम एक कड़ा चेतावनी पत्र तक आ गया कि यदि उसने मुनीष को कुछ कहा तो उल्टे उसी के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसी धमकी को फलीभूत करते हुए एक कर्मठ एवं ईमानदार डीईओ का न केवल यहां से तबादला कर दिया गया बल्कि परेशान करने के इरादे से बेमतलब की जांचें भी शुरू कर दी गई। मुनीष के हौंसले तो देखिये 14 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 16 तारीख तक भी डीईओ की कुर्सी पर जमी बैठी है। जानकार बताते हैं कि इसी दिन उसके पति धर्म सिंह व दो अन्य सारा दिन मुनीष के दफ्तर में कमरा बंद करके बैठे रहे। यह सब उनका राजनीतिक रसूख भी है जो अब तक उसे गिरफ्तार करना तो दूर पद से हटाया भी नहीं गया।

हर तरह से नालायक, निकम्मी एवं भ्रष्ट होने के बावजूद जिस अधिकारी को इतना प्रोत्साहन मिलता रहा हो, जिसके खिलाफ़ होने वाली हर शिकायत को दबा दिया जाता रहा हो तो उसका दिमाग तो खराब होना ही था। इसी के चलते मुनीष ने कभी अफसरों को अफसर और मातहतों को गुलाम से अधिक कुछ नहीं समझा। सदैव खुले खेत में बेफिक्री से चरती रही।

27 लाख की क्रेन आयेगी तो सड़कों से जाम हटेगा

जब नौ मण तेल होगा, तभी राधा नाचेगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) निकम्मे प्रशासन के पास काम न करने के लिये बहानों की कोई कमी नहीं है। ये लोग धरातल पर काम करने की बजाय काम को टरकाने के नये-नये बहाने बुनने में लगे रहते हैं।

शहर भर की शायद ही कोई भीतरी सड़क अवैध पार्किंग के चलते संकरी न हो गई हो जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। शासन-प्रशासन के पास, अवैध रूप से सड़क घेरने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिये भारी मात्रा में पुलिस बल भी है। लेकिन जब कोई काम करने की नीयत ही न हो तो तमाम अधिकार और बल किसी काम के नहीं।

27 लाख की क्रेन से यह ट्रक हिलेंगे भी नहीं

इसी सप्ताह, अवैध पार्किंग से निपटने के लिये स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने 27 लाख की क्रेन खरीदने के लिये टेंडर जारी करने की बात तो ऐसे कही है जैसे कि उस क्रेन के न होने से ही अवैध पार्किंग वालों ने सड़कों को जाम कर रखा है और उसके आते ही समस्या स्वत: हल हो जायेगी। आखिर ये अधिकारी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? शहर भर की सड़कों पर हजारों छोटे-बड़े वाहन सड़कों को घेरे खड़े रहते हैं। क्या उस अकेली क्रेन के आने से तमाम वाहन अवैध पार्किंग छोड़ देंगे? नहीं। फ़िर यह कहा जायेगा एक क्रेन बेचारी क्या-क्या करे? इसके लिये तो 10-20 क्रेनें और चाहिये। फ़िर आये दिन वे क्रेने मोरम्मत के लिये वर्कशापों में खड़ी रहेगी और अवैध पार्किंग ज्यों की त्यों चलती रहेगी।

सरकार द्वारा खरीदारी करने के शौक का दूसरा नमूना, सड़कों पर झाड़ू लगाने से उठने वाली धूल से पर्यावरण को बचाने के नाम पर नगर निगम ने भी विदेशों की तर्ज पर स्वचालित सक्शन मशीने खरीदी अथवा महंगे भाड़े पर ले रखी हैं। झाड़ू लगाने वाले यह मशीने यदा-कदा सड़कों पर टहलती नजर आ जाती है। गौरतलब है कि झाड़ू से उठती धूल तो प्रशासन को नजर आ गई लेकिन टूटी सड़कों से उड़ते धूल के गुबार नजर नहीं आते।

स्मार्ट सिटी कंपनी बीते लगभग चार साल से 2700 करोड़ से अधिक रुपया ठिकाने लगा चुकी है इसके बावजूद शहर को न तो जल भराव से छुटकारा मिला और न ही उफनते सीवरों से। खस्ता हाल सड़कों की हालत बद से बद्तर होती जा रही है। पैदल चलने वालों को फुटपाथ नहीं और न ही कोई सायकिल ट्रैक। खुले में शौच जाते लोग शहर की समार्टनेस की हकीकत बयां करने को पर्याप्त हैं। हां, टेंडर जारी करने व तरह-तरह की खरीदारी करके बजट को ठिकाने लगाने की पूरी महारत इस कंपनी को है।